post. They have accordingly recommended his name for the post to the concerned administrative Ministry. The existing procedure requires the administrative Ministry concerned to furnish vigilance clearance of candidates recommended by the PESB before forwarding the name/names for consideration of ACC. Vigilance aspects are looked into by the PESB, during the process of selection, only to the extent specifically brought to its notice.

(c) and (d) Do not arise.

संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार

428. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार के कितने मामले लाए गए हैं ;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में किस प्रकार के आरोप थे और दोषी व्यक्तियों को क्या-क्या सजा दी गई; और

(ग) भ्रष्टाचार से प्रभावित लोगों को क्या-क्या रियायतें दी गईं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती मारग्रेट आल्वा : (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों में, संघ लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित एक मामले में जो कि आयकर/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इत्यादि, निरीक्षक परीक्षा 1988 के प्रश्न पत्र के लीक होने में कर्मचारी चयन आयोग के तीन कर्मचारियों की तथाकथित भागीदारी संबंधित थी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की गई और उसने इन तीन कर्मचारियों के विरुद्ध केवल विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की

शेष दो मामलों में कर्मचारी चयन, आयोग के समूह "घ" के दो कर्मचारी आयोग की परीक्षा में छद्म रूप से बैठाने में सहायता संबंधी कार्यवाही की कोशिश करने में लिप्त पाए गए। उन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

गुजरात में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

429. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के भरूच, सूरत, बड़ोदरा और पंचमहल जिलों को लक्ष्यानुसार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों को वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त जिलों के कितने गांवों को लाभ मिला है/लाभ मिलने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री उत्तम भाई पटेल : (क) केन्द्रीय और राज्य बजट में उपलब्ध कराई गई निधियों के अनुसार लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किये जाते है। जिलावार लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा तय किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा इनकी निगरानी रखी जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा ही इन्हें रखा जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियों के आंकड़े रखती है

जबकि रूप से गुजरात राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों के लक्ष्य नीचे दिये गए हैं :—

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य (संख्या)	राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य (संख्या)
1991–92	4977	25000
1992–93	2489	15000
1993–94	5367	15000
1994–95	25000 (केन्द्र और राज्य के संयुक्त लक्ष्य)	

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रही जनसंख्या को मुहैया कराये जाते हैं न कि पूर गांव को।

राज्य में कवर की गई कुल जनसंख्या 46.54 लाख है अथवा 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की 270.35 लाख की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 17.20 है। भावी कवरेज केन्द्रीय तथा राज्य बजट में निर्धारित निधियों के अनुसार होगी।

Development of Backward/Tribal Areas of Gujarat

430. SHRI GOPAL SINGH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any specific action plan for the development of backward rural and tribal areas of Panchmahal, Surat; Bharuch and Dang districts in Gujarat;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the year-wise details of the amount allocated for the development of these areas during the last three years; and

(d) what is the category-wise and and year-wise number of beneficiaries in these districts of Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) For developmtnt of backward rural and tribal areas of various States/UTs, the Government of India has launched Intensified Jawahar Rozgar Yojna (IJRY) in 120 selected backward districts of the country since 1993-94. Six districts, including Panchmahal and Surat of Gujarat are also covered under this programme. Besides, Employment Assurance Scheme (EAS) with the objective of providing assored employment for 100 days in casual manual work to all able bodied persons in the rural areas of the country, who are in need of work and seeking for it has been launched since 1993-94. This scheme is implemented in 1778 Revamped Public Distribution System (RPDS) blocks of the country. In the State of Gujarat EAS is being implemented in 97 RPDS blocks of 16 districts. EAS is bting implemented in 11 blocks of Panchmahal district,